शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 3 ■ अंक 06 ■ सितम्बर 2019 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 36

भारतीयता के दो स्वर

गांधी और दीनदयाल

परिषद गतिविधि

हिमाचल प्रदेश : प्रांतस्तरीय जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते वक्ता एवं मंचासीन अतिथि

राजस्थान : छात्रसंघ चुनाव में जीत के बाद विजयी मुद्रा में छात्र नेता एवं अभाविप कार्यकर्ता

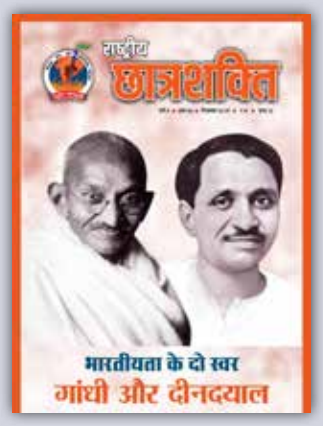

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा–क्षेत्र की प्रतिनिधि–पत्रिका

वर्ष 3, अंक 05
सितम्बर, 2019

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक–मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298

rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

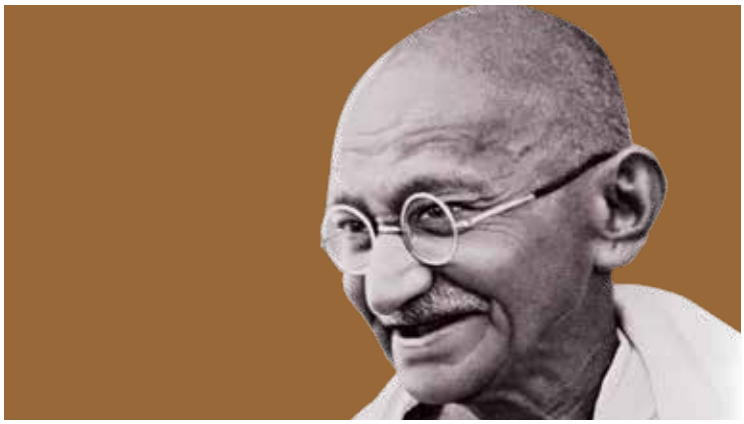

05 सम्मोहन नहीं, सृजन और संकल्प चाहिए

महात्मा गांधी का आकलन सम्मोहन की स्थिति में करना गांधीवादी सत्य के साथ अन्याय करने जैसा होगा। यह...

संपादकीय	04
दीनदयाल उपाध्याय और जम्मू–कश्मीर	08
स्मृति शेष : संगठननिष्ठ अरूण जेटली	11
अरूण जेटली का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति : अभाविप	12
अरूण जेटली की कहानी उनके साथी हेमंत विश्नोई की जुबानी	13
ज्ञानोत्सव–2019: शिक्षा में भारतीयता, ज्ञान और विकास के लिए जरूरी : भागवत	15
ABROGATION OF ARTICLE 370: A WATERSHED MOMENT FOR INDIA'S KASHMIR STORY AT INTERNATIONAL FORA	16
NATIONWIDE 'SELFIE WITH CAMPUS UNIT' OF PARISHAD AT A GLANCE	22
नई सदी में छात्र – छात्राओं को खड़ा करने का अभियान है सेल्फी विद कैंपस	24
बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे आपटे जी : होसबाले	25
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर हो मंथन	26
विकास ऐसा हो जिसमें किसी का आत्मविश्वास न टूटे : श्रीनिवास	28
राजस्थान : छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने लहराया जीत का परचम	29
हिमाचल प्रदेश: प्रांत स्तरीय जनजातीय छात्र सम्मेलन सोलन में संपन्न	30
स्वतंत्रता दिवस की 73 वीं वर्षगांठ पर अभाविप ने निकाली तिरंगा रैली	31
असम : त्रुटिहीन एनआरसी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभाविप कार्यकर्ता	32
परिचर्चा : क्या हांगकांग में जारी छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार पाने में सफल होगा?	33

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

श्री अरुण जेटली नहीं रहे। अभाविप का एक कार्यकर्ता, जिसने अभाविप के विभिन्न दायित्वों पर रह कर संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान किया हो, स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे कठिन दौर में संगठन का नेतृत्व किया हो, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता न करने के कारण कीमत चुकाने को हमेशा तैयार रहा हो, संगठन के निर्देश पर हाथ में आती हुई सत्ता को छोड़ने का साहस दिखा सकता हो, कार्यकर्ताओं के लिये ऐसे प्रेरणास्रोत का जाना पीड़ादायी है।

अरुण जी की वाक्पटुता, तीखे तर्क, सौम्य भाषा और आकर्षक व्यक्तित्व सहज ही सबको प्रभावित करते थे। इस सब से इतर उनमें एक प्रखर लेखक और संपादक भी छिपा था। इसका साक्षात्कार छात्रशक्ति के उन पुराने अंकों को पलटते हुए किया जा सकता है जिनका संपादन अरुण जी ने किया। भाषा का प्रवाह और तीखे तेवर इन अंकों की विशेषता रही।

अरुण जी छात्रशक्ति के संस्थापक संपादक रहे और अनेक वर्षों तक यह दायित्व निभाते रहे। उनका जाना जहां देश के राजनैतिक क्षितिज पर एक शून्य का निर्माण करने वाला है, वहीं छात्रशक्ति के लिये यह अपूरणीय क्षति है।

सितम्बर माह भारतीयता के पुनर्स्मरण का अवसर लेकर आता है। 11 सितम्बर को स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो की ऐतिहासिक धर्मसंसद में भारतीय जीवन और दर्शन को प्रतिपादित कर सम्पूर्ण जगत को सम्मोहित कर लिया था। 14 सितम्बर को हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अतएव यह भारतीय भाषाओं को उपयुक्त स्थान देकर विदेशी बोझ को उतार फेंकने के अवसर के रूप में इसे देखा जाना चाहिये। यद्यपि इस दिशा में अदिक प्रगति नहीं हो सकी है किन्तु एक राष्ट्रवादी सरकार के कार्यकाल में हम इसे भी होता देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

25 सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्तूबर को महात्मा गाँधी की जयंती हमें स्वदेशी चिंतन का स्मरण कराती है। महात्मा गाँधी के जीव के 150 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं। दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर जैसी श्रृंखला प्रकाशित की थी वैसी ही लेख-माला छात्रशक्ति ने महात्मा गाँधी के जीवन के अनेक अछूते बौद्धिक और दार्शनिक पहलुओं को एक श्रृंखला के रूप में अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत की। विश्वास है कि यह उपयोगी सिद्ध हुई होगी।

कश्मीर पर देश ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी सुखद परिणति राष्ट्रीय एकात्मता के रुप में सामने आये इसकी प्रतीक्षा है। देश भर के विश्वविद्यालयों के परिसरों में यह समय हलचल भरा है। सभी जगह छात्र-संघ चुनावों की गहमा-गहमी है। सभी ओर से कुछ खट्टे-मीठे समाचार प्राप्त होंगे। जिनकी सूचना अगले अंक में आप तक पहुंचेगी।

शुभकामना सहित,

आपका
संपादक

महात्मा गांधी की सार्धशती पर
विशेष आलेख श्रृंखला - 11

सम्मोहन नहीं, सृजन और संकल्प चाहिए

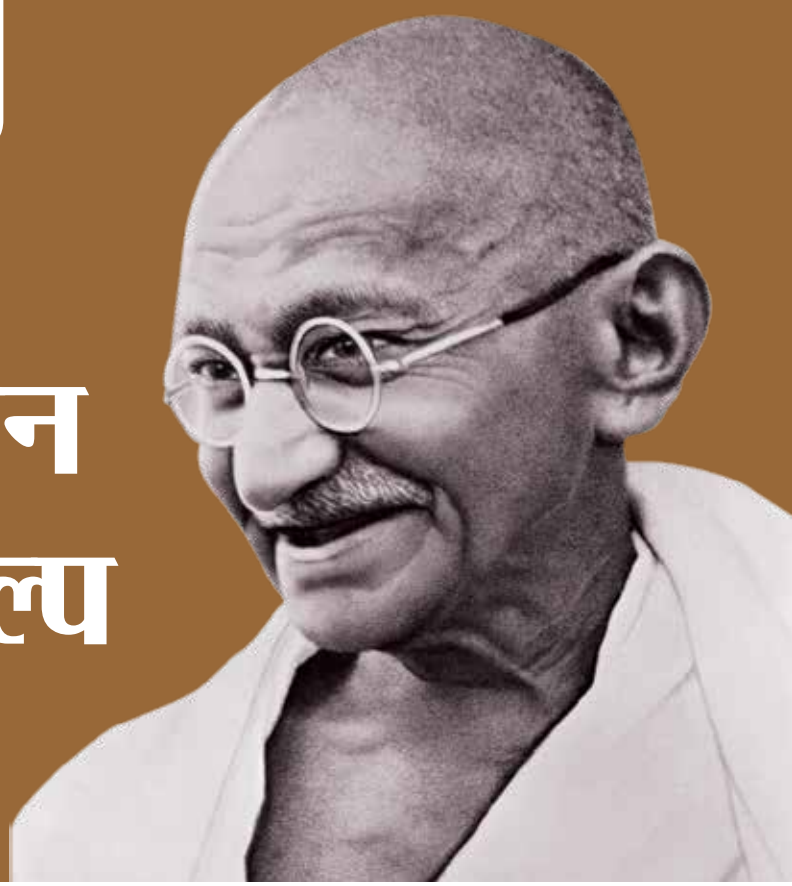

डा. जयप्रकाश सिंह

महात्मा गांधी का आकलन सम्मोहन की स्थिति में करना गांधीवादी सत्य के साथ अन्याय करने जैसा होगा। यह सम्मोहन उनके पक्ष में भी हो सकता है और उनके विपक्ष में भी। सब-कुछ हां या ना में देखने वाली दृष्टि प्रायः घटनाओं को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखती। इस कारण, किसी घटना को लेकर झट-पट अपने निष्कर्ष निकाल लेती है। जबकि होता यह है कि व्यक्ति की मान्यताएं-स्थापनाएं एक देश-काल में अभिव्यक्त होती हैं और इस कारण शत-प्रतिशत शुद्ध रूप में किसी व्यक्ति की आस्था-मान्यता का अभिव्यक्त होना नामुमकिन ही है। सार्वजनिक जीवन में तो आस्थाओं-मान्यताओं के विशुद्ध रूप में अभिव्यक्त होने की संभावना शून्य ही रहती है।

गांधी को जो देश-काल मिला था, उस समय भारत का राष्ट्रीय और सांस्कृतिक-बोध रसातल में पहुंच चुका था। सार्वजनिक जीवन में भारतीयता और भारतीय शब्दावली का राजनीति की मुख्यधारा में उपयोग लगभग वर्जित था। जो राजनेता ऐसा करते थे, उन्हें प्रतिगामी, पिछड़ा कहकर हासिए पर धकेल दिया जाता था। गांधी इस देश काल की सीमा में भारत और भारतीयता के प्रतीक बने। इसलिए उनमें सनातन धर्म के सारे मूल्यों की खोज करना या भारतीयता की सर्वोत्कृष्ट आदर्शों की अपेक्षा करना भी बेमानी है।

विभाजन के दौरान गांधी को 'वन मैन आर्मी' कहा गया था। लेकिन सांप्रदायिकता के संदर्भों में ही नहीं अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में गांधी 'वन मैन आर्मी' थे। भारतीयता को समझने उसके अनुसार रणनीति बनाने और सही ढ़ंग से उसके क्रियान्वयन के मोर्चे पर भी गांधी 'वन मैन आर्मी' के तौर पर कार्य कर रहे थे। उन्हें एक ऐसा जनमानस मिला था, जो गरीब और निरक्षर था। जो लगभग बारह सौ सालों से निरंतर विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था। इतने लंबे संघर्ष के कारण उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। इस समाज का आत्मबल भी प्रायः समाप्त हो चुका था। ऐसे समाज से संवाद करना, देशभक्ति और सांस्कृतिक

मूल्यों को लेकर आग्रह करना एक जटिल और दुरूह कार्य था। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए भारतीय मूल्यों का उपयोग किया। गांधी ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि एक हद तक इसे अंजाम तक भी पहुंचाया।

भारतीय जनमानस में गहराई तक धंसे आदर्शों एवं शब्दावली को नए संदर्भों में स्थापित करना, भारतीयों में आत्मबल भरने को एक महा-अभियान के तौर पर लेना चाहिए। वह प्रतीकों में निहित सामर्थ्य को अच्छी तरह से जानते थे। उनका बहुत सटीक ढंग से उपयोग किया। लेकिन प्रतीकों की लड़ाई की अपनी सीमाएं तो होती है, गांधी की कार्य-शैली में भी वैसी सीमाएं दिखती हैं।

भारतीय जनमानस में गहराई तक धंसे आदर्शों एवं शब्दावली को नए संदर्भों में स्थापित करना, भारतीयों में आत्मबल भरने को एक महा-अभियान के तौर पर लेना चाहिए। गांधी जी प्रतीकों में निहित सामर्थ्य को अच्छी तरह से जानते थे। उनका बहुत सटीक ढंग से उपयोग किया।

देश-कालगत बाध्यताओं, दार्शनिक अपूर्णताओं एवं रणनीति-गत सीमाओं के बावजूद गांधी समकालीन परिस्थितियों में प्रस्थान बिंदु हैं। आज भारत के पास अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा है, भारत-भारतीयता को लेकर शोध की एक श्रृंखला जन्म ले रही है, रणनीति को अपने मूल्यों से जोड़ने का काम अधिक सृजनात्मक तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब यह नही कि गांधी के पक्ष या विपक्ष में सम्मोहित होकर ही विचार किया जाए। उसे एक-दम से स्वीकार कर लिया जाए या सिरे से नकार दिया जाए। यह सरल कार्य है। लेकिन ऐसा करना इतिहास के प्रति असम्मान जैसा होगा और इतिहास को झुठलाना हमेशा स्वयं के लिए ही नुकसानदायक होता है।

गांधी उन विलक्षण नेताओं में से एक थे जो एक साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर सक्रिय थे। और उनकी उपस्थिति की तीव्रता इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से महसूस की जा सकती है। केवल उपस्थिति ही नहीं हर जगह भारतीयता का आग्रह भी स्पष्ट रूप से दिखता है। संभवत इसी कारण उन्हें भारतीय समाज में इतनी गहरी स्वीकृति मिली।

गांधी का भारतीय चित्ति के साथ एक हद तक तादात्म्य है। इसी कारण वह भारतीय जनमानस का व्यापक स्तर पर संवेदित कर, अपने संदेशों को सफलता के साथ लोगों तक पहुंचा पाए। यदि कहीं भारतीय चित्ति और गांधी के चिंतन में तादात्म्य नहीं दिखता, तो वह त्यागा जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा है। वह यह कि क्या अब तमाम दावों के बावजूद भारतीय चित्ति के साथ भारतीय जनमानस का तादात्म्य बढ़ा है? क्या तकनीकी प्रभावों ने और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय चित्ति को

लोगों की आंखों से और भी ओझल नहीं कर दिया है? प्रश्न तो यह भी उठता है कि जो आवाजें गांधी के पक्ष या विपक्ष में उठती हैं, उनकी जीवनशैली और जीवन दर्शन में भारतीय चित्ति को कितना स्थान मिला हुआ है? गांधी को सिरे से खारिज करने वाली आवाजों को एक बार ठंड़े दिमाग से यह जरूर सोचना चाहिए कि उनके भावुक नारों के कारण कहीं भारतीय चित्ति और सनातन धारा को ही तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है? गांधी को उस अनुपात में तो स्वीकार किया ही जाना चाहिए जितना उनका भारतीय चित्ति के साथ तादात्म्य है।

गांधी यह सिखाते हैं कि सनातन की आराधना कोई कालवाह्य होने-पाने आराधना नहीं है। अनुभूति के स्तर पर सनातन-काल वाह्य हो सकता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति समय सापेक्ष ही होगी। देश काल की सीमा में आने के बाद सनातन की संपूर्णता भी प्रभावित होती है, और कुछ हद तक वह सीमित हो जाता है। सनातन का अनुभव एवं अभिव्यक्ति में जिस स्तर तक समानता रहती है, भारतीय चित्ति उस स्तर तक ही व्यक्ति की उत्कृष्टता को स्वीकार करती है। उसके जीवन को प्रामाणिक मानती है। सामान्य शब्दों में इसे मन-वचन-कर्म की ऐक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

सनातन की समय सापेक्ष साधना के प्रतीक हैं महात्मा गांधी। इस प्रक्रिया में उनकी तमाम सीमाएं स्पष्ट हैं, फिर भी इस साधना में गांधी से जो सूत्र मिलता है, वह एक तरह से आत्म-संधान का सनातन मूल्य है। गांधी निरंतर सृजनशील हैं, और अपनी मान्यताओं के लिए संकल्प-बद्ध भी। वह बन बनाए रास्ते पर नहीं चले।

सनातन की समय सापेक्ष साधना के प्रतीक हैं महात्मा गांधी। इस प्रक्रिया में उनकी तमाम सीमाएं स्पष्ट हैं, फिर भी इस साधना में गांधी से जो सूत्र मिलता है, वह एक तरह से आत्म-संधान का सनातन मूल्य है। गांधी निरंतर सृजनशील हैं, और अपनी मान्यताओं के लिए संकल्प-बद्ध भी। वह बन बनाए रास्ते पर नहीं चले। व्यक्ति की अद्वितीयता, मार्ग की अद्वितीयता की भी मांग करती है। उन्होंने अपने रास्ते बनाने की कोशिश की। उपलब्ध संसाधनों का सृजनात्मक उपयोग किया और लक्ष्य को लेकर संकल्प-बद्ध भी रहे।

संकल्प और सृजन इस सृष्टि की सर्वाधिक मूलभूत प्रक्रियाएं हैं। इन्हीं के आधार पर सृष्टि अस्तित्व में भी आती है, और संचालित भी होती है। गांधी के जीवन में भी यह दोनों मूल्य बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उनसे संकल्प और सृजन का बोध अपनाने के बाद उनकी सीमा-सामर्थ्य की चर्चा के लिए खुला स्पेस देने के लिए परहेज करने का कोई कारण नजर नहीं आता। ■

(लेखक हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं।)

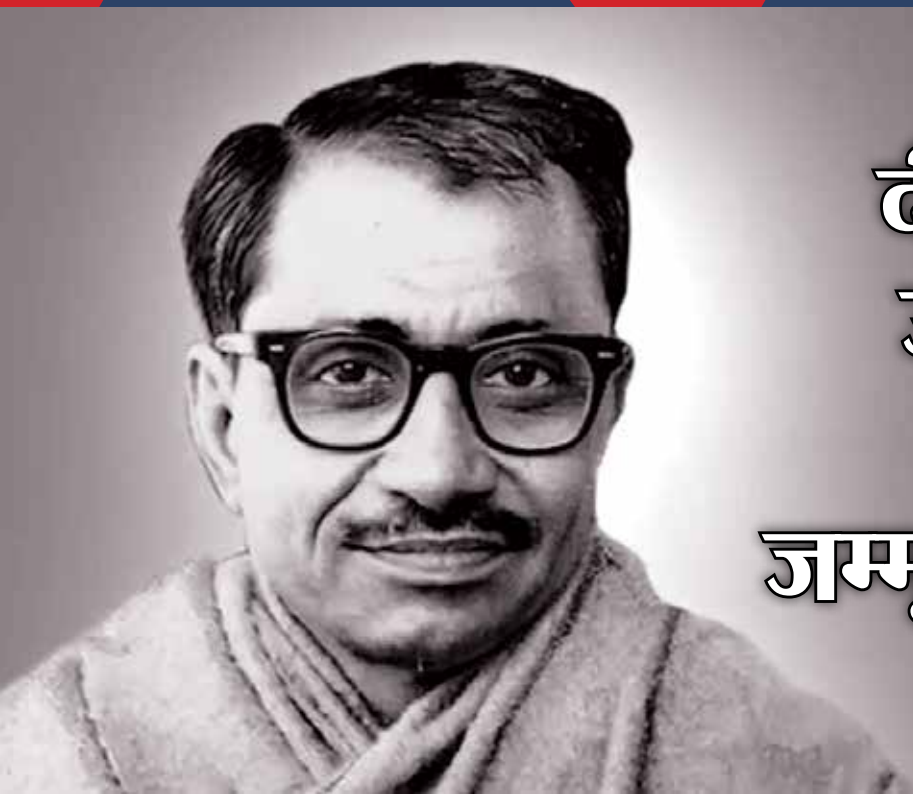

दीनदयाल उपाध्याय और जम्मू-कश्मीर

देवेश खंडेलवाल

अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने का फायदा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को ही मिलने वाला है। अब वहां स्थानीय लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष नही करना पड़ेगा, क्योंकि भारत का संविधान उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 370 कोई कानून नहीं बल्कि सजा के तौर पर 1949 से सहन किया जा रहा था। इसकी जानकारी बहुत ही सीमित है कि इन दोनों केंद्र शासित राज्यों को उनका वास्तविक हक दिलाने में भारतीय जनसंघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके सूत्रधार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और बाद में इस प्रक्रिया में दीनदयाल उपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जम्मू-कश्मीर के साथ भारत का अधिमिलन अन्य रियासतों के सामान ही हुआ था। फिर भी, शेख अब्दुल्ला की व्यक्तिगत जिद्द को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू किसी भी हद्द तक जा सकते थे। उनके सहयोगी और करीबी गोपालस्वामी आयंगर ने 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 संविधान सभा के समक्ष पेश किया। दस्तावेजों और पत्रों के अनुसार अनुच्छेद के कई मसौदे तैयार किये गए थे। शुरुआत में यह एकदम विभाजनकारी था। सरदार वल्लभभाई पटेल के हस्तक्षेप के बाद उन मसौदों में कई परिवर्तन किये गए, जिससे यह अपेक्षाकृत पहले से कमजोर हो गया था।

आईसीएस अधिकारी वी. शंकर का सरदार पटेल के साथ काम करने का लंबा अनुभव रहा था। वे लिखते है कि अनुच्छेद 370 की स्वीकृति पर उन्होंने सरदार से नाराजगी जताई। जिसपर सरदार ने कहा, "अंततः न तो शेख अब्दुल्ला स्थाई है और न ही गोपालस्वामी। भविष्य, भारत सरकार की ताकत और हिम्मत पर निर्भर करेगा। यदि हम अपनी ही ताकत पर विश्वास नहीं कर सकते तो, तो हम एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व के योग्य नहीं है।"

दुर्भाग्यवश सरदार पटेल का निधन दिसंबर 1950 में

हो गया। आखिरकार, शेख ने अनुच्छेद 370 के बहाने जम्मू-कश्मीर को स्वायत्त बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। भारतीय संविधान में निहित मौलिक एवं नागरिक अधिकार, वित्तीय एकीकरण, सीमा शुल्क का उन्मूलन, उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, चुनावों का संचालन और भारत के ध्वज की सर्वोच्चता जैसे प्रावधान से राज्य के नागरिकों को वंचित कर दिया गया।

सरदार पटेल की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी सबसे पहले भारतीय जनसंघ ने ली। जनसंघ की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक ने 10 फरवरी, 1952 को प्रस्ताव पारित किया, "जम्मू-कश्मीर राज्य का भी भारत के साथ उसी प्रकार का पूर्ण विलय करना चाहिए, जिस तरह भारत संघ में सम्मिलित सभी राज्यों का किया गया है।"

शेख और प्रधानमंत्री नेहरू दोनों का रवैया एकदम नकारात्मक था। आखिरकार जब सभी कोशिशें असफल हो गयी, तो 6 मार्च को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यह सत्याग्रह राज्य के विषयों पर जागरूक कराने का अभियान था। इस सत्याग्रह का केंद्र तो दिल्ली था, लेकिन सबसे ज्यादा सत्याग्रही उत्तर प्रदेश से थे। दीनदयाल उपाध्याय को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गयी थी। उन्होंने वहां दर्जनों जन-सभाओं को संबोधित किया। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी, रामभाऊ म्हालगी, विजय कुमार मल्होत्रा, कुशाभाऊ ठाकरे, प्रेमनाथ डोगरा, यू.एम. त्रिवेदी, केदार नाथ सहानी, बलराज मधोक, सुन्दर सिंह भंडारी और भैरों सिंह शेखावत भी अन्य राज्यों में मौजूद थे। जनसंघ के वार्षिक प्रतिवेदन में दीनदयाल उपाध्याय ने बताया कि सत्याग्रह में कुल 10,751 सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया था।

इस स्थिति ने केंद्र सरकार को असहज कर दिया। इसलिए हज़ारों की संख्या में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार जनसंघ की सभाओं में भारी भीड़ रहती थी। जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय के समाधान खोजते हुए डॉ. मुखर्जी का श्रीनगर में बलिदान हो गया। इस क्षति के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने शेख को अगस्त 1953 में गिरफ्तार कर लिया। जनसंघ ने सत्याग्रह भी वापस ले लिया गया। इसी के साथ शेख का स्वायत्त कश्मीर घाटी का सपना भी खत्म हो गया।

राज्य की कमान बक्शी गुलाम मोहम्मद के हाथों में आ गयी। दीनदयाल उपाध्याय लगातार अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सरकार से जवाब मांगते रहे। उन्होंने 1 लाख से अधिक पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। अनुच्छेद 35A ने उनके मौलिक अधिकार छीन लिए थे। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से निर्वाचित प्रतिनिधि भेजने की मांग दीनदयाल उपाध्याय ने की। एक सजग विपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में कई लेख लिखे।

> जनसंघ का मनोबल कभी कम नही हुआ। उनकी हर केंद्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुच्छेद 370 को हटाने पर प्रस्ताव पारित किये गए। कानपुर में 15 जनवरी, 1966 को केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल थे। इस समिति ने भारत का पूर्ण संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया।

देश की एकता को सुनिश्चित करने में जनसंघ को सबसे बड़ी सफलता 1959 में मिली। इस साल राज्य के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण अधिनियम स्वीकृत किये गए। जनसंघ ने देशभर में 8 फरवरी, 1959 को 'कश्मीर दिवस' मनाने का फैसला लिया था। परिणामस्वरूप परमिट व्यवस्था 1 अप्रैल, 1959 को समाप्त कर दी गयी। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय वहां की विधानमंडल ने 1 अप्रैल, 1959 को किया जोकि 26 जनवरी, 1960 को लागू हो गया। हालांकि, यह सभी प्रावधान अनुच्छेद 370 के कारण वहां लागू नहीं हुए थे। दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जब जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है तो भारतीय संविधान वहां पूरी तरह से लागू होना चाहिए।"

हालांकि, अनुच्छेद 370 की समाप्ति की दिशा में

यह एक अभूतपूर्व कदम था। दीनदयाल उपाध्याय कभी संसद सदस्य नहीं रहे, लेकिन जनसंघ ने कई बार इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। 13 फरवरी 1964 में मंदसौर से सांसद यू.एम. त्रिवेदी लोकसभा में एक प्रस्ताव पर बोल रहे थे। इस दिन जम्मू-कश्मीर पर चर्चा का विषय नही था। बावजूद इसके त्रिवेदी ने जोर देते हुए केंद्र सरकार से पूछा, "अनुच्छेद 370 को समाप्त करने में क्या अड़चन आ रही है?"

इस साल अनुच्छेद 370 को हटाने पर विपक्ष एकजुट हो गया था। जनसंघ ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। इस तीसरी लोकसभा में प्रकाशवीर शास्त्री ने 11 सितम्बर को अनुच्छेद 370 पर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, "जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति से संबधित भारतीय संविधान की धारा 370 हटा दी जाए।" शास्त्री ने निजी विधेयक पेश किया था। जनसंघ के हुकम चंद कछवाय ने समर्थन देते हुए कहा, "सभापति महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस सबंध में सरकार की नीति बहुत ही गलत रही है। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए।" केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए विधेयक के विरोध में व्हिप जारी कर दिया गया।

जनसंघ का मनोबल कभी कम नही हुआ। उनकी हर केंद्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुच्छेद 370 को हटाने पर प्रस्ताव पारित किये गए। कानपुर में 15 जनवरी, 1966 को केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल थे। इस समिति ने भारत का पूर्ण संविधान जम्मू-कश्मीर पर लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया।

दीनदयाल उपाध्याय 1967 में कालीकट के अधिवेशन में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों के तरह भारत से जोड़ने की बात कही। उनका राजनैतिक जीवन बहुत लंबा नही था। मुगलसराय (पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन) के पास 11 फरवरी, 1968 को उनकी हत्या कर दी गयी। इस दिन एक दूरदर्शी नेता, कुशल लेखक, ओजस्वी पत्रकार और सफल सगंठनकर्ता का निधन जरूर हुआ था लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहे। ■

स्मृति शेष : अरूण जेटली

संगठननिष्ठ अरूण जेटली

| रामबहादुर राय |

श्री अरुण जेटली के सफल और सार्थक जीवन का संदेश क्या है? वह सुनने में अत्यंत सरल है। लेकिन उसमें जीवन जीने की कला है। ऐसा मंत्र है जो अरुण जेटली को जानने-समझने और उनसे प्रेरणा लेने में हमेशा सहायक होगा। वह इन थोड़े से शब्दों में समाया हुआ है- अपना कार्य समझ लें और उसे पूरे कर्म कौशल से निभाएं। यह सोचकर ही मन विह्वल हो जाता है कि वे शरीर से नहीं रहे। अशरीरी हो गए।

राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महती भूमिका के लिए अरुण जेटली जिन बड़े कार्यों के आधार पर याद किए जाएंगे, उसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में की। दिल्ली विश्व विद्यालय छात्र संघ की छवि उन्होंने चमका दी। पहले वह धूमिल थी। सच कहें तो कलंकित थी। सत्ता की चेरी के रूप में छात्र जगत में जानी जाती थी। अरुण जेटली ने उसे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हरावल दस्ता बना दिया। वे दिन थे, जेपी आंदोलन के। जिसमें संपूर्ण क्रांति और समग्र क्रांति के सपने पल रहे थे। कोई छात्र नेता जो बरायनाम भी होगा, वह कैसे इस सपने से अपने को दूर रख सकेगा! अरुण जेटली तो निर्वाचित नेता थे। जिस छात्र नेता ने छात्र राजनीति को राष्ट्रीय महिमा और गरिमा दी, उसके बारे में भ्रमवश या ईर्ष्यावश अक्सर कहा जाता है कि वे लोकसभा का चुनाव एक बार भी जीत नहीं सके। यह कथन राजनीतिक नासमझी का है।

6 मार्च 1975 को दिल्ली में जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार आंदोलन के समर्थन में एक रैली हुई जिसमें शिरोमणी अकाली दल, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस संगठन आदि के बड़े नेता शामिल हुए थे । रैली के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामनंदन मिश्र, मधु के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया था। आमतौर पर ज्ञापन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है । इसके पीछे तर्क था कि हम जनता के द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि के अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन सौंप रहे हैं । उसी दिन शाम में जेपी द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान में चुने गये छात्रनेताओं की बैठक बुलाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर 'छात्र संघर्ष समिति' बनाई गई जिसके राष्ट्रीय संयोजक अरूण जेटली एवं सह संयोजक तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आनंद कुमार को बनाया गया ।

अरुण जेटली वीर पुरुष थे। ईमानदार ही वीरता का वरण करता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण 26 जून, 1975 का है। लोकतंत्र का गला घोटा गया। तानाशाही थोपी गई। पूरे देश में गहरे अंधकार का सन्नाटा छा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही उस अभिशाप को मिटा देने का पहला पराक्रम आप जानते हैं, किसने किया? वे अरुण जेटली थे। इसका उल्लेख कई पुस्तकों में है। लेकिन उस पराक्रम को वे उल्लेख समझाते कम हैं,

पाठक को भ्रमित ज्यादा करते हैं। वे बताते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में मात्र दो सौ छात्र ही विरोध में उतरे, जिसका नेतृत्व अरुण जेटली कर रहे थे। जिसने इमरजेंसी को झेला है, देखा है और मन की पीड़ा से उपजी बगावत मोल ली है, वे ही जान सकते हैं कि इमरजेंसी के पहले दिन इतने छात्रों का विरोध वह भारत की पहली घटना थी। वे दो सौ छात्र पूरी छात्र शक्ति के प्रतिनिधि थे। संख्या पर नहीं, उनके साहस को याद किया जाना चाहिए। साहस तो वास्तव में संपन्न माता-पिता की संतान अरुण जेटली ने दिखाया था। उसकी सजा काटी। इमरजेंसी भर जेल में रहे। एक मई, 1977 को नानाजी देशमुख की सलाह पर जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अरूण जेटली को युवा जनता का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। किसी भी छात्र नेता के लिए वह आत्म गौरव का क्षण होगा। जिसे अरुण जेटली ने विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व की सलाह पर अस्वीकार किया। प्रश्न सैद्धांतिक जो था। वह अरुण जेटली का त्याग भी था।

एक अनकही कहानी कहना जरूरी है। 1987 का साल राजनीतिक संकट का जितना राजीव गांधी के लिए था, उससे अधिक वह बड़े संवैधानिक संकट की छाया में था। एक दिन अरुण जेटली ने मुझे एक दस्तावेज दिया। उसे वकील राम जेठमलानी ने बनाया था, जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के लिए था। जिसके आधार पर वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बर्खास्त करने का इरादा बना चुके थे। वह दस्तावेज 29 मार्च, 1987 को नवभारत टाइम्स में छपा। जो उस समय की बड़ी संवैधानिक दुघर्टना को टालने में सहायक हुआ। इसी विचार से अरुण जेटली ने उसे दिया भी था। बहुत बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वीकार किया कि ज्ञानी जैल सिंह 'प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बर्खास्त करने का संवैधानिक आधार' खोज रहे थे। वह घातक कदम होता। जिसे अरुण जेटली की सूझबूझ से रोका जा सका। उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को उस साजिश में न पड़ने की सलाह दी थी। जिसे उन्होंने माना भी।

ऐसी अनेक घातक राजनीतिक घटनाओं को अरुण जेटली ने कब-कब रोका और कैसे राजनीति की धारा को बदल दिया, इस पर भविष्य में अनेक शोध होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ही एक संक्रमणकालीन दौर 2013 में था। नेतृत्व के प्रश्न को जिस राजनेता ने चुपचाप हल करवाया वे कोई दूसरे नहीं, अरुण जेटली ही थे। उसकी कुछ बातें प्रसंगवश मुझे मालूम है। उन बातों के बारे में लिखने का फिर कभी समय जरूर आएगा। ■

अरूण जेटली का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अरूण जेटली के निधन पर शोक प्रकट की है। अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष तथा भारत सरकार में पूर्व वित्त व कानून मंत्री रहे श्री अरुण जेटली जी का असामयिक निधन देश के साथ - साथ विद्यार्थी परिषद् के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अभाविप के पैनल से वर्ष 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़कर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और देशभर में अभाविप के नेतृत्व पर समाज का विश्वास सुदृढ़ हुआ।

अभाविप में लंबे समय तक कार्य करते हुए माननीय अरुण जी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व अन्य दायित्वों का भी निर्वहन किया। उन्होंने 1973 में देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित प्रखर हुए जन आंदोलन 'नव निर्माण आंदोलन' को नेतृत्व प्रदान करने के साथ ही वर्ष 1974 में आयोजित हुए जे.पी. आंदोलन में भी प्रमुख सहभागिता निभाई। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस-नहस कर वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इमरजेंसी के दौरान माननीय जेटली 19 महीनों तक जेल में बंद रहे।

उन्होंने एक प्रसिद्ध वकील होने के साथ ही एक प्रबुद्ध राजनेता के रूप में समय-समय पर देश की सेवा की। आज देशभर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता श्री अरूण जेटली के निधन पर शोकमय है, इन दुखद क्षणों में भारी मन से उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से उन्हें अपने श्री चरणों मे स्थान देकर दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करने की कामना करता है।

माननीय जेटली जी के असामयिक निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस. सुब्बैया, राष्ट्रीय महामंत्री श्री आशीष चौहान तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने गहरा शोक प्रकट करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। ■

अरूण जेटली की कहानी उनके साथी हेमंत विश्नोई की जुबानी

श्री अरूण जेटली का 66 वर्ष की आयु में निधन न केवल उनके परिवार की क्षति है बल्कि देश, समाज और भारतीय जनता पार्टी के साथ - साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की भी भारी क्षति है । उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करके दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया और छात्र जगत में लोकप्रिय होते गये । इसी दौरान वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के संपर्क में आये । संघ और जनसंघ की वैचारिक पृष्ठभूमि न होने पर भी विद्यार्थी परिषद् ने उनके गुणों के आधार पर उन्हें कॉलेज छात्रसंघ से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ में 1972 में उपाध्यक्ष और 1973 में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़वाया । मैं (हेंमत कुमार विश्वनोई) भी उनकी टीम में महासचिव पद पर उम्मीदवार बना था । यह टीम नाम की दृष्टि से भी विलक्षण थी । इनमें ए से अरूण जेटली, बी से बिन्दल विजय, वी से विश्नोई हेमंत के साथ पी से (सुश्री) पुर्णिमा सेठी थे। भारी मतो से चुनाव इस टीम ने जीता और एबीवीपी का गौरव बढ़ाया ।

श्री जेटली यहां नहीं रूके । देश की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ पहले गुजरात और बाद में बिहार के आंदोलन को दिल्ली के छात्रों ने राष्ट्रव्यापी बनाया । दिल्ली में अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन किया जिसे श्री जयप्रकाश नारायण ने संबोधित किया । विश्वविद्यालय छात्रसंघ में भी श्री जेटली के नेतृत्व में तय किया कि किसी छात्र के गलत दाखिले या फेल को पास करने के किसी मामले पर हम दखल नहीं डालेंगे । चुनाव के बाद कार्यकाल बीतने में अधिक समय नहीं लगा लेकिन वर्तमान सरकार के खिलाफ देश भर में छात्र आंदोलन खड़े हो गए । इस कारण तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होने पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई । सभी प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के साथ छात्र नेताओं को 25 जून की रात गिरफ्तार करने का प्रयास किया । अरूण जी के के घर भी पुलिस गई लेकिन रात को उनके वकील पिता ने पुलिस को घुसने नहीं दिया । समचार पत्रों पर रोक के कारण प्रायः व्यक्तियों के आपातकाल का एहसास नहीं था अगले दिन श्री जेटली ने विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों को एकत्र किया और विरोध प्रदर्शन किया । उन्हें वहां से गिरफ्तार कर पहले तिहाड़ जेल और वहां से अन्य नेताओं के साथ अंबाला जेल भेज दिया । उनकी यह जेलबंदी 25 जनवरी 1977 तक चली ।

मैं, बाद में भूमिगत कार्यों के कारण 15 अक्टूबर 1975 को पुलिस के हत्थे चढ़ा । मेरे और जेटली के खिलाफ आंदोलन के कारण दो दर्जन अन्य मुकदमें भी दर्ज थे । इस कारण उन्हें अंबाला जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में हमारे साथ लाया गया । इस 19 मास

की जेल यात्रा में श्री जेटली ने कभी भी मुक्ति की चिंता नहीं की । आनंद से साथ खेलकूद, पढ़ाई और बाहर से आने वाले बढ़िया खाने के साथ समय व्यतीत किया । मेरा वजन जेल जाने के समय 55 किलो था जो रिहाई तक 70 किलो हो गया था । इसी तरह स्थिति द्वय सभी नौजवानों और छात्र नेताओं की थी ।

जेल में जाने से पहले उनका लॉ का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया था लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित श्री जेटली लॉ और राजनीतिक विषयों का गंभीरता से अध्ययन करते रहे। भारत के संविधान सभा की डिबेट की प्रस्तावों को पढ़ते रहते थे । इतना ही नहीं परीक्षा देने के लिए पैरोल की याचिकाएं भी दिल्ली हाइकोर्ट में दायर करते रहे । जेल से बाहर आने के बाद, अनेक राजनेता श्री जेटली और मुझे राजनीति में सक्रिय कर लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे लेकिन जेल में ही गहराई से चिंतन कर हमने तय किया था पहले अपने कामकाज में स्वयं को स्थापित करेंगे और फिर राजनीति में जायेंगे । इसी कारण श्री जेटली को तत्कालीन जनता पार्टी अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नामांकित किया था लेकिन श्री जेटली ने विद्यार्थी परिषद् नेतृत्व से राय करके उस पद से इस्तीफा दे दिया था । ऐसा था उनका संगठन के प्रति समर्पण ।

मैं पत्रकारिता में आ गया और जेटली जी अधिवक्ता बन गए । मेरे पास भी हाइकोर्ट और उच्चतम न्यायालय की रिपोर्टिंग का काम होने से उनसे लगातार मिलना रहा। बाद में वह राजनीति के शिखर की ओर बढ़ते गए लेकिन हमारा राजनीतिक विषयों पर चर्चा का क्रम बना रहा। एक बार मैं उनके कैलाश कॉलोनी वाले घर गया तो उन्होंने हमारी स्वर्गवासी साथी पूर्णिमा सेठी के परिवार की चिंता करने का अनुरोध किया । मैंने पता किया तो कोई राजनीतिक नेता पैसे की उगाही के लिए उन्हें परेशान कर रहा था । इससे पूर्णिमा सेठी जी की बहने आंतकित थी । पत्रकार होने के कारण, उस नेता की गतिविधियों पर रोक लगाना मेरे लिए कठिन नहीं था और मैंने वैसा ही किया । इससे पता चलता है कि श्री जेटली न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं की बल्कि उनके न रहने पर उनके परिवारों की भी चिंता करते थे।

दिल्ली में चुनाव के दौरान उनसे एक बार भेंट हुई । मुझे आश्चर्य हुआ कि विधानसभा की 70 सीटों के संभावित उम्मीदवारी में रहने वाले 4 -5 नेताओं के नाम और उनकी पृष्ठभूमि की उन्हें पूरी जानकारी थी । ■

ज्ञानोत्सव–2019 : शिक्षा में भारतीयता का एहसास

शिक्षा में भारतीयता, ज्ञान और विकास के लिए जरूरी : भागवत

"प्रत्येक राष्ट्र की एक अलग पृष्ठभूमि, विभिन्न मूल्यों, विभिन्न परिदृश्य और अलग संस्कृति है। इसलिए, पूरी दुनिया के लिए एक शिक्षा नीति नहीं हो सकती है।अन्य राष्ट्रों की एक नीति भारतीय शिक्षा नीति नहीं हो सकती है यदि उसमें भारतीयता नहीं है। हमें अपनी शिक्षा नीति की आवश्यकता है क्योंकि हमारे राष्ट्र का दृष्टिकोण और आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। रा. स्व. संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारतीय शिक्षा प्रणाली और भारतीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "शिक्षा में भारतीयता की उपस्थिति मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान और विकास के लिए बहुत जरूरी है।" चर्चा का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा ज्ञानोत्सव 2019 के तहत किया गया था।

श्री भागवत ने कहा कि शिक्षा पेट भरना नहीं है। "यह शिक्षा के बारे में बहुत संकीर्ण सोच है। इसमें बड़ी क्षमता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में अपने लक्ष्य का एहसास कराना है। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है और हमें आगे बढ़ते रहना होगा। यह सभी शिक्षकों की दृष्टि होनी चाहिए जब वे पढ़ाने जाते हैं, छात्रों की दृष्टि जब वे सीखने जाते हैं, तो माता-पिता की दृष्टि जब वे अध्ययन के लिए अपने वार्ड भेजते हैं और स्कूलों के प्रधानाचार्यों की दृष्टि। इसके बाद ही हम शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता को आगे बढ़ा पाएंगे। '' उन्होंने कहा कि शिक्षा संतुलित होनी चाहिए। समकालीन विषयों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इन मूल्यों और भारतीय मूल्यों के ज्ञान के साथ। तभी इसे संतुलित शिक्षा कहा जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई शिक्षा नीति में भारतीय भावना के साथ इन सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

सरसंघचालक ने बताया कि शिक्षा किसी व्यक्ति को सभी झोंपड़ियों से मुक्त करती है और उसे स्वतंत्र बनाती है और उसकी वास्तविक क्षमता को सामने लाती है। तभी व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। "हमारी शिक्षा में भारतीत्व होना चाहिए। यदि हम संस्कृति, भोजन और त्योहारों को शामिल नहीं करते हैं, तो शिक्षा अधूरी है। शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य में देश की विविधता और समृद्ध संस्कृति शामिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा, समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, जिन पर हमें दृढ़ रहना है और जो हमारे भारतीय होने का आधार है।

दो दिवसीय ज्ञानोत्सव -2019 का पहला आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) में हुआ था, जिसमें शिक्षा सुधार से जुड़े भारत भर के शिक्षाविदों ने भाग लिया था। दूसरा समारोह पूसा संस्थान में आयोजित किया गया। शुरुआत में, श्री अतुल कोठारी ने चर्चा की कि शिक्षा में विकृतियों के खिलाफ शिक्षा बचाओ आंदोलन कैसे शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि पहली बार शिक्षा चर्चा का विषय बनी। यह महसूस किया गया कि पाठ्यक्रम से केवल विकृतियों को हटाने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी तरह शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की स्थापना हुई। न्यास का लक्ष्य हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया विकल्प प्रदान करना है। यह न केवल शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा करता है बल्कि समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है। देश के वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा की संरचनाओं पर उन्होंने कहा कि यह प्रतिस्पर्धी संरचना ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी, जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों से अधिक नहीं चाहते थे और अब तक हमारे पास एक ही प्रणाली है जिसमें बहुत कम परिवर्तन हुए हैं। ■

Abrogation of Article 370:
A watershed moment for India's Kashmir story at international fora

Dr Swadesh Singh

The Kashmir issue turned controversial when Pandit Jawaharlal Nehru approached the United Nations for mediation with Pakistan over a territory acquired by the newly created state. Pakistan occupied a big chunk of Kashmir known as Pakistan Occupied Kashmir, Gilgit and Batalistan.

We have witnessed that in the last 70 years, Pakistan has managed to registere a diplomatic win by claiming that Kashmir is a bilateral issue in which it is a party along with India. Pakistan has never missed out on any chance to flag the issue of Kashmir on international forums like United Nations, G-20, Organization of Islamic Cooperation, NAM, SAARC etc.

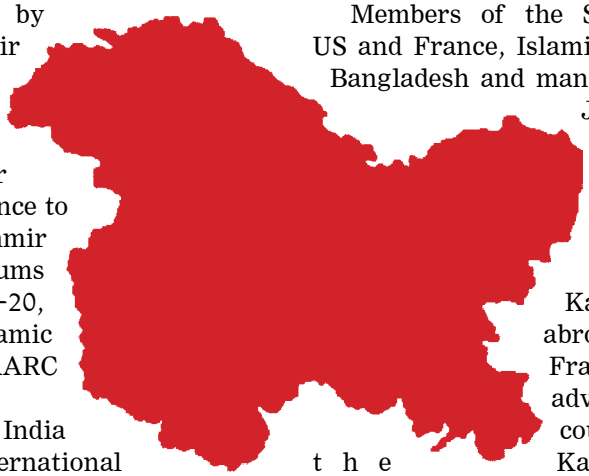

If on the one hand India tried to convince international fraternity that Kashmir is an internal matter and integral part of India, on the other hand Pakistan tried to convince the international community that Kashmir is a controversial and bilateral issue which is an unresolved fallout of Partition and which should be resolved in favour of Pakistan.

For the first time in the political history of independent India, a major step on Kashmir was taken by the government of India. A constitutional amendment was brought in Article 370 making it ineffective and Article 35A was abrogated by a presidential order. Now, Kashmir does not enjoy any special privileges.

When India took this step, the international community either kept quiet or supported the Indian move as it was aimed at ensuring gender equality, social justice and development for a region that had not been fully integrated and that had been kept away from the wave of development because of one temporary provision.

Members of the Security Council like US and France, Islamic countries like UAE, Bangladesh and many other countries like Japan, South Korea supported this move by India.

The United States said that there was no change in its policy on Kashmir following the abrogation of Article 370. France's foreign minister advised his Pakistani counterpart to address the Kashmir issue through dialogue with India.

UAE said in a statement that the reorganisation of states is not a unique incident in history of independent India and it was mainly aimed at reducing regional disparity and improving efficiency. The country called it an internal matter as stipulated by the Indian Constitution.

Following the abrogation of Article 370, for the first time Pakistan was isolated at international level. The only country that

came in support of Pakistan was China. And even as China initially supported Pakistan on the matter, it slowly distanced itself from the issue.

This step of the Government of India proves that Kashmir is an internal matter of India and no one, including Pakistan, has the right to speak on it. The silence and support extended by the international community has been a big diplomatic win for the Indian side. India has been able to convince the world that Kashmir is an integral part of the country and during constitution framing, a temporary provision was introduced which is now being diluted. As a sovereign state, India has all the rights to amend her constitution.

With this move the Indian leadership and diplomacy has taken a giant step forward in the Kashmir issue. The defence minister Rajnath Singh said that there would be no talks with Pakistan on Kashmir now but on Pakistan occupied Kashmir (POK).

Union home minister Amit Shah has said in Parliament that there will be no talks with the separatist Hurriyat Conference and declared that India will continue to claim the territories of Jammu and Kashmir in Pakistan-occupied Kashmir (PoK) and Aksai Chin.

Foreign Affairs minister Jai Shankar also rejected Pakistan Prime Minister Imran Khan's offer of "conditional talks" over the Kashmir issue. In an interview given to a newspaper in Brussles Jaishankar said India would not be able to think of dialogue when Pakistan "openly practices terrorism".

Few years back, Prime Minister Narendra Modi raised the issue of human rights violation in Baluchistan from the Red Fort. He urged the international community to pay their attention to those issues. On Kashmir, Prime Minster said that abrogation of Article 370 was a historic decision that will ensure equal rights and duties for the citizens of Jammu, Kashmir and Ladakh. PM Modi also asserted that the decision has amounted to the realisation of dreams of many of the distinguished leaders of the past.

The step taken by the Modi government is not only a big domestic move but internationally it also brought clarity on the issue of Kashmir. Now with this move, international fraternity has also come to clearly understand that Kashmir is an internal matter of India. The environment of confusion and pacifism created during the last 70 years forbade us from even imagining a scenario where a temporary provision on Kashmir could be removed so easily by a presidential order. How could we expect the international community to understand the issue and our stand on it, when we ourselves were in a blur.

BY THE ABROGATION OF ARTICLE 370 THE GOVERNMENT OF INDIA LED BY PRIME MINISTER NARENDRA MODI HAS CREATED A WATERSHED MOMENT THAT HAS CLEARED THE AIR ON KASHMIR, INDIA'S CLAIMS AND PAKISTAN'S OCCUPATION. THE ISSUE NOW IS THE PART OF KASHMIR WRONGFULLY OCCUPIED BY PAKISTAN AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY HAS GOT THE STORY STRAIGHT THIS TIME.

By the abrogation of Article 370 the Government of India led by Prime Minister Narendra Modi has created a watershed moment that has cleared the air on Kashmir, India's claims and Pakistan's occupation. The issue now is the part of Kashmir wrongfully occupied by Pakistan and the international community has got the story straight this time. ■

(Author teaches Political Science in Delhi University)

परिसर परिसर

#SelfiewithcampusUnit
DEPARTMENT OF COMPUTER APPLICATIONS
ABVP AGRA
#SelfiewithcampusUnit
ABVP

परिषद

परिसर परिसर

परिषद

Nationwide 'Selfie with campus unit' of Parishad at a glance

Dr.Tushaar Kanti Acharjee

In the recently concluded special drive of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad namely 'selfie with campus unit' across the country has successfully influenced an applausive number of students from almost all the sectors of educational institutions which is as high as Fifty thousand. Such a drive has covered right from the 10+ standard of students and has witnessed overwhelming responses among the students and it is firmly believed that students have got chances to interact with the higher authorities of their institutions in resolving the issues in various respects like Lavatories, Drinking water storage, sanitation, cleanliness and appropriate schooling.

The best outcome of the vigorous campaign has unfolded issues even at the schools of very remote areas where the confidence levels of students have come up to a notable standard at which they could strive to resolve the burning issues of their educational institutes on own.

Moreover; the world's largest students organisation has not left any impediment unturned getting penetrated among the minds and million hearts of the students of even northeast besides the whole nation too .The most astonishing thing about the North east region's inhabitants is that amidst the series of most beautiful and incredible landmarks and heavenly beauties mostly they lack in confidence and generate less optimism in most of the materialistic possession. But since the inception of penetration of the superior ideological thoughts of ABVP into the minds of students, the most powerful strength and future prospect of our nation has remarkably changed. The nicest thing is ,the mindsets of students who are considered as the future sailor of nation have changed in all the eight states of the most resourceful region of our country what is surely unknown by 85% of Bharatiya Citizens.

Among the series of reforming and productive karyakram (activities)of ABVP the most sizzling one is "SELFIE WITH CAMPUS" which happens to be the buzz in every students mind.

Relevantly, this year also the nationwide,"selfie with campus unit" has drawn the attention of uncountable exciting hearts in almost every school, college and University campus what started right from Arunachal Pradesh, the land of rising sun or the dawn-lit mountains' .All-round participation has been found among the students in the largest state of Northeast too. The outcome of what is as.total no of HS School covered 60, College campuses 23 and university campuses as many as 5.The overall involvement of the students from irrespective of class,status and community have motivated towards the patriotic characteristics by the super influential ideology of ABVP.

Next comes, Manipur which literally means 'the Jewelled land' happened to be the birthplace of Pulo (presently called Polo). The Imphal Polo Ground which is the oldest polo ground in the world. In the state of Manipur,in 30 numbers of schools ,17 colleges and 5 university campuses there was the torrent of "Selfie with Campus" .The expressions of the various levels of students -fraternity proclaims that such a campaign helps mingle with each other and breaks the socio economic barrier .This campaign

has particularly enabled us to know each other and strive to resolve any issues of out colleges which were left ignored for long. So we have been into team spirit now.

Mizoram is another smallest state in India which is especially known as the 'Songbird of India'; Mizoram is one of the smallest states in India. Phawngpui is the highest mountain peak in Mizoram, rising about 2157 metres high near the Myanmar border is famous for Mizoram has had world famous kinds of orchids what is unknown to almost 90% of us. In the concerned "Selfie with campus "drive Mizoram school and college units could reach up to 3 numbers of college and 01 school only by dint of some issues over there stated by the concerned person.

Tripura is another small state is largely forested and very popular for Orange Gardens, Pineapple Gardens, Rubber Gardens, Rubber Nursery, Bamboo plantation, Tea Plantation, Jute Cultivation, and Paddy Fields. Tripura is known for its largest primate diversity in the country. Although the state of Tripura is comprised of eight districts yet the torrential flow of the power of idealistic ABVP has totally motivated and trained the students with the culture, customs and conduct of its kinds. In a very short span of just one or years the total numbers of membership has ascended up to 32000 which were initiated from a very negligible figure. In the "selfie with campus" steer almost all levelled students was noticed with full spirit and zeal in the stipulated time ,the campaign could touch as high as 154 schools,19 colleges and 1 university.

We all wait till the report of mega city declares so is the state Assam ,which boldly holds the gateway to all other states of Northeast and Assam is known to be the mother of a few other states of the region. Assam has been blissfully graced with some natural gifts like possessing Majuli the largest river island in the world and smallest (inhabited) river island in the world, Umananda also called 'Peacock island'. Assam has the largest population amongst the rest states in the region around 3.55 crores.

Throughout the 32 districts of Assam , in the vigorous campaign of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parisad's "selfie with campus" has successfully touched 191 schools,145 colleges and 05 universities, a total no of 341 institutions. The noteworthy outcome of the "selfie with Campus"in the state of Assam shows us an inspiring and motivational perspective to go a few steps further with the sacred ideology based on 'Knowledge, Character and unity' ABVP admires and pledges to nationalism and patriotism.

Akhil Bhartiya Vidyarthi Parisad has been at high vigil especially focussing on the educational institutions with one prime mission which is to convert or transform every individual student to a perfect and ideal citizen of our nation which had been tortured, oppressed and stressed at the time of the inhumane and atrocious rule and regime of Mughal and Britishers.We look forward to organise such nationwide campaign among the students of all levels to motivate and inspire them to inherit patriotism and nationalism. Join ABVP with a special resolution to devote to national reformation and replacing our omnipotent Bharat to the supreme place. ■

नई सदी में छात्र - छात्राओं को खड़ा करने का अभियान है सेल्फी विद कैंपस

| आशीष चौहान |

दो दिवसीय बैठक पूर्ण कर मैं बैंगलुरु के मुख्य रेलेवे स्टेशन के परिसर पहुंच चुका था, बैंगलुरु के एक कार्यकर्ता ने फोन कर मुझे, मेरी गाड़ी के बारे में पूछा, वह भी रेलेवे स्टेशन के दूसरी ओर था। पलेटफार्म नं. 8 पर खड़ी दिल्ली जाने वाली राजधानी की ओर बढ़ा तो वह कार्यकर्ता मिला। बातचीत के दौरान पता चला कि उसका नाम तेजस है और बैठक में आये अभाविप कार्यकर्ताओं की व्यवस्था करने का दायित्व है। उन्होंने मुझे बताया कि पिछली बार कर्नाटक प्रांत वर्ग के विजयपुर (बिजापुर) में भेंट हुई थी। बातचीत व परिचय के बाद मैंने तेजस को कहा कि अब तो मैं अपनी सीट पर पहुंच गया हूं और कुछ समय में रेल भी निकलेगी और वह भी वापस जा सकता है। निकलने से पूर्व उसने एक सेल्फी खींचने का आग्रह किया और उसने अपने मोबाईल से मेरे साथ मुस्कुराती हुई फोटो (सेल्फी) खींची। तेजस ने सेल्फी मुझे भेजने की बता कही। आज मोबाईल के अच्छे कैमरे और सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव, हम भी प्रत्येक सुअवसर को याद करने के लिए चित्र खींचते हैं परंतु सेल्फी तो एक कदम आगे जाकर हम सभी की यादगार मिलने जुलने के अनुभव, अलविदा करने का ही पर्याय बन चुका है। मिलेनियलस (सन 2000) के आस-पास जन्मे, प्रतिदिन औसतन सेल्फी खींचते हैं। गत वर्ष में अभाविप ने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं देशभर के माध्यमिक महाविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के साथ संवाद खड़ा करने की योजना की। कार्यकर्ता परिसरों में गये, महाविद्यालयों के होनहार विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और ख्याति प्राप्त विद्यार्थियों से भेंट की। प्राध्यापकों, प्राचार्यों के साथ चर्चा की और अपने अनुभव सोशल मीडिया में शेयर किए और साथ ही एक सेल्फी भी डाली जिसने पूरे अनुभव को जीवंत कर दिया। देश भर में 46000 से अधिक संस्थानों (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, +2 स्कूल परिसर भवन) के सामने गेट पर विद्यार्थियों के खिलते चेहरे इस अभियान का बखान कर रहे थे। सेल्फी के माध्यम से नये सम्पर्क परिसरों में विद्यार्थीयों के साथ अभाविप का संपर्क स्थापित हुआ। छात्राओं ने 30 अक्टूबर को देश भर में सभी जिलों में आयोजित मिशन साहसी में बढ़ - चढ़ कर भाग लिया। छात्राओं को स्वरक्षा के गुर सिखाते हुए अंतर्निहित साहस को जगाने का कार्य किया। सात लाख से अधिक छात्राओं तक पहुंचा यह अभियान अपने आप में एक अलग मानक है। ग्रीष्म शिविरों में आयोजिन होने वाले यह अभाविप प्रशिक्षण सत्र, देश भर के 500 से अधिक जिलों में आयोजित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व 'नेशन फर्स्ट - वोटिंग मस्ट' अभियान के तहत विद्यार्थी परिषद् ने युवाओं को शत प्रतिशत मतदान करने व 'नोटा नहीं ' की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में सामाजिक अनुभूति कार्यक्रमों का प्रांतो में आयोजन हुआ है। सत्र प्रारंभ हो चुका है, परिसरों में वर्ष भर सक्रिय रहने वाली विद्यार्थी परिषद् पुनः परिसरों में हेल्पडेस्क लगा रही है। कुछ प्रांतों में सदस्यता अभियान अपने जोरों पर है। विद्यार्थी दिवस, 9 जुलाई को देश भर हुए कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया - फेसबुक, ट्विटर, इन्सटाग्राम पर डाला। #StudentsDay भारत में ट्विटर ट्रैंड भी रहा। अब विद्यार्थी परिषद् ने पुनः परिसरों में जाने का अभियान लिया है। वर्ष भर छात्रों के विषयों को उठाते हुए कुछ सामाजिक, राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, इस वर्ष सेल्फी विद कैम्पस अभियान में परिसरों में परिषद् नेतृत्व को खड़ा कर रही है। अपनी कार्यपद्धति के अनुरूप वर्ष भर संपर्क में विद्यार्थियों को प्रेरित कर 1 - 10 अगस्त महाविद्यालय कार्यकारिणी घोषणा अभियान आयोजित किया है। पूरे जुलाई माह में प्रांत - प्रांत में बैठके, योजना हेतु प्रवास तथा अंतिम कार्यकर्ता का संपर्क का दायित्वों की घोषणा करना इस अभियान का अभिन्न अंग है। जहां यह अभियान विगत वर्ष की 9000 से अधिक महाविद्यालय इकाईयों को सेल्फी विद कैम्पस अभियान के 46000 संख्या के दूरी को पाटने का अभियान है वहीं देश में सतत् संपर्क में रहने वाले व अपने कार्य में आने वाले लगभग 15000

परिसरों (जिनसे कभी न कभी कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का सहभाग रहता है) को सशक्त कर आधिकारिक इकाई में लाने का प्रयास है।

अभाविप का प्रत्येक पदाधिकारी इस अभियान में परिसरों में गये। नवनिर्माण से लेकर स्टेट कैंपस आंदोलन हो या शिक्षा के व्यापारिकरण की लड़ाई, परिषद सदैव आंदोलन की धूरी रही है। इन्हीं परिसरों की बानगी बयां करने हेतु सेल्फी विद कैम्पस अभियान, सशक्त विद्यार्थी परिषद् कार्यकारिणी निर्माण का कदम है। जिसमें एक परिसर इकाई का मॉडल प्रस्तुत करते हुए इस अभियान की परिधि तय हुई है। मुझे विश्वास है कि इस अभियान को अगर मैं फिल्मरोल कैमरे की तकनीक में कहें तो हम negative से चित्र की धुलाई के काल में हैं और आज के डिजिटल जमाने में तो वह सेल्फी खींचने से पूर्व के काउंटडाउन पर है। देशभर से आने वाले जानकारी, सेल्फियों की बाढ़ में छात्र आंदोलन को अगले स्तर पर ले जाने का अवसर खड़े होंगे जहां 15 करोड़ युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् अपने संकल्पित कदम बढ़ाएगी। ■

(लेखक अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री हैं।)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' सितंबर 2019 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/rashtriyachhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे आपटे जी : होसबाले

'स्व. बालासाहब आपटे जी का युवाशक्ति में गहरा विश्वास था। वे हमेशा कहते थे कि युवाओं का अनुभव कम है, उनकी आयु कम है, इस कारण उनका पीछे रहना तर्कसंगत नहीं। देश के युवा, विद्यार्थी परिवर्तन का माध्यम हैं। राष्ट्र निर्माण के कार्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र नागरिक के रूप में देखना चाहिए। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले ने कही । वे 'प्रो. बाल आपटे सेंटर फॉर स्टडीज इन स्टूडेंट्स एंड यूथ मूवमेंट' केंद्र के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जाने-माने विधिज्ञ, विद्यार्थी आंदोलन के आधार, दिशा देने वाले शिक्षातज्ञ, अच्छे सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और अपने शब्द को प्रमाण मानकर चलने वाले स्व. बालासाहेब आपटे जी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे प्रत्यक्ष कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, विद्यार्थी एवं युवा आंदोलन की जानकारी, युवा संगठन का तत्वज्ञान सर्वसामान्य लोगों तक ले जाने का काम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने कहा कि हम परिवर्तन के दौर में हैं। भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या युवा है। 2020 में भारत की औसत आयु 29 वर्ष यानी अमेरिका और चीन से आठ वर्ष कम होगी। ऐसे में इस युवाशक्ति को योग्य दिशा में प्रवाहित करना आवश्यक है। वहीं अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि समाज के विकास, मानव कल्याण के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर सक्षम बनाना आवश्यक है। प्रो. बाल आपटे सेंटर फॉर स्टडीज के माध्यम से विद्यार्थियों से संबंधित विषय का अभ्यास होगा। इस शोध का उपयोग समाज के लिए नीतियां बनाने के लिए होगा। मुझे विश्वास है कि यहां से प्रशिक्षित होने वाला विद्यार्थी वर्ग नेतृत्व करेगा और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। ■

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर हो मंथन

| अतुल कोठारी |

पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहीं पर किसी ने विरोध नहीं किया। इस शिक्षा नीति का देश भर में स्वागत हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नीति का विरोधियों ने भी विरोध नहीं किया। भाषा के नाम पर थोड़ी बहुत दक्षिण भारत में हुआ है वह भी सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि वहां के कुछ गिने चुने राजनेताओ के द्वारा। सरकार के इस पहल का स्वागत करना चाहिए। योगेन्द्र यादव जैसे लोग ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा है कि पहली बार भाषा की बात हुई है। सरकार को इस मुद्दे पर अपना पैर पीछे नहीं खिंचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मसौदे को भारतीयता के प्रकाश में रखकर तैयार किया गया है।। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में पश्चिम केन्द्रीत शिक्षा नीति चल रही थी, सच कहें तो मैकाले शिक्षा पद्धति को बदलने की दिशा में पहली बार कोई प्रयास हुआ है। तीसरी बात यह है कि इस नीति पर जितनी बहस हुई है इससे पहले कभी किसी नीति पर नहीं हुआ। यह तीसरी बार है जब सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और अच्छी बात यह है कि लोग भी बढ़ - चढ़कर अपना सुझाव सरकार को दे रहे हैं। मसौदे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की बात कही गई है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् भी मांग करते आई है, इस बात का इसमें स्वीकार किया है। कई बार हमलोग व्याख्यानों/संगोष्ठियों में कहते थे कि निजी विद्यालयों को पब्लिक स्कूल नहीं कहा जाना चाहिए। दुनिया भर में सरकारी स्कूल को ही पब्लिक स्कूल कहा जाता है लेकिन हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही थी यहां पर प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल लिखते हैं। जिसे बंद करने की बात भी इस नीति में कही गई है। दूसरा विद्यालय स्तर पर ढ़ांचागत और पाठ्यक्रम के स्तर पर परिवर्तन की बात कही गई है। पहले छः वर्ष से शिक्षा आरंभ हो रहा था जिसे इस नीति में तीन साल से शुरू करने की वकालत की गई है। यानी मौजूदा 10 + 2 मॉडल की जगह 5 + 3 + 3 + 4 का वैज्ञानिक ढ़ांचा लाने की सिफारिश की गई है जो बच्चों के संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास की अवस्थाओं पर आधारित है। इसमें आयु के हिसाब से बदलाव किया गया है। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक करने की बात की गई है यानी तीन साल से आठ वर्ष की आयु पूर्व प्राथमिक, नौ से ग्यारह आयु को प्राथमिक, बारह से चौदह माध्यमिक और चौदह से अठारह वर्ष की अवस्था को उच्चतर माध्यमिक होगा। प्रथम चरण में औपचारिक शिक्षा नहीं देना है। उन्हें खेल, संगीत इत्यादि के माध्यम से सिखाने की बात की गई है जिसे बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कक्षा छः से उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दिया जायेगा जिसे बाद में छात्रों की इच्छानुसार बृहद किया जायेगा। नौंवी के बाद विषयों का प्रतिबंध नहीं रहेगा, छात्र अब मर्जी का विषय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 40 विषय है, छात्र उन 40 में से इच्छानुसार किसी पांच विषय को चुन सकते हैं। विषयों का जो बोझ था उसे दूर करने की कोशिश की गई है। कुछ विषय है जिस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय स्तर पर जब सेमेस्टर सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा है तो विद्यालय स्तर पर यह कितना सफल होगा कहना मुश्किल है। वर्तमान जो ढ़ांचा बनाया गया है उसमें एक साल की शिक्षा बढ़ जायेगी,यह लोगों के बीच स्वीकार्य होगा या नहीं, विमर्श का विषय है। उच्च शिक्षा के स्तर पर भी ढ़ांचागत सुधार की बात कही गई है जिसका मैं स्वागत करता हूं। स्नातक को चार वर्षीय किया गया है जिसमें छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसमें व्यावहारिक पक्ष को तवज्जो दी गई है। स्नातक में अगर कोई एक वर्ष पढ़ना चाहता है, पढ़ लिया या फिर किसी कारण वश छोड़ दिया है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल करेगा तो डिप्लोमा की डिग्री दी जायेगी, तीन वर्ष में स्नातक की एवं चार वर्ष पूर्ण करने पर बैचलर ऑफ लिबरल आर्टस की डिग्री दी जायेगी, जिसको

परास्नातक के समकक्ष समझा जायेगा। बैचलर ऑफ लिबरल आर्टस की डिग्री मिलने के बाद छात्र सीधे शोध कार्य में कर पीएचडी कर सकते हैं। बीएड को चार वर्ष करने का सुझाव दिया है, वह भी स्वागतयोग्य है। जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा के बारे में जो छोटा – मोटा विरोध हुआ जो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित था। क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है चूंकि 1968 के शिक्षा नीति में यह पहले से वर्णित है। 2005 में भी इसी बात को दोहराई गई थी लेकिन 2005 में इस मसले पर किसी ने विरोध नहीं किया और आज वे विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करना था तो उस समय भी करते, उस समय क्यों नहीं किये ! मकसद साफ है उन्हें सिर्फ राजनीति करना है। दूसरी बात यह है कि जो लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं वे अपने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में रख रहे हैं। 60 के दशक की बात कुछ और थी आज कुछ और है। 1960 के समय ज्यादातर लोग अपने गांव और शहर में रहते थे उन्हें बाहर से ज्यादा काम नहीं पड़ता था। आज दुनिया बदल चुकी है। उदाहरण के लिए अगर एक असम का छात्र गुजरात पढ़ने जायेगा तो वह कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। गुजराती उसे आती नहीं, अंग्रेजी स्थानीय लोग नहीं समझेंगे तो हिन्दी से ही काम चलाना पड़ेगा और इस बात को पढ़ने वाले छात्र अच्छी तरह से समझ रहे हैं इसलिए समाज स्तर पर हिन्दी का कहीं विरोध नहीं हुआ। जहां तक हिन्दी को थोपने की बात है उसके लिए सरकार को मेरा एक सुझाव है कि कि छात्रों को आठवीं अनुसूचि में शामिल कुल 22 भाषा एवं अंग्रेजी (क्योंकि अंग्रेजी मजबूरी बन गई है) में अपने पंसद के तीन भाषा को चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अपने स्थानीय भाषा के अलावा उसे जिस दो भाषा को पढ़ना है, पढ़ेगा। इस प्रकार जिसे हिन्दी पढ़ना होगा वह हिन्दी चुनेगा, जिसे संस्कृत पढ़ना होगा वह संस्कृत चुनेगा। ऐसा करने पर विवाद ही खत्म, सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है लोगों के ऊपर जबरन अंग्रेजी थोपी जा रही है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस शिक्षा नीति में संस्कृत पर काफी अच्छी – अच्छी बात कही गई है लेकिन यह बढ़ेगा कैसे? कोई ठोस नीति निर्धारित नहीं है। सरकार से मेरी मांग होगी कि संस्कृत को बढ़ाने की दिशा में ठोस नीति बनाई जाये साथ ही त्रि-भाषा सूत्र को दशवीं तक लागू किया जाय ताकि छात्र ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं को सीख सके।

रोजगारपरक शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा को लेकर मसौदे में व्यावहारिक पक्ष का उल्लेख किया गया है यानी व्यावासिक शिक्षा अब स्वैच्छिक न होकर नियमित शिक्षा में समावेशित की जायेगी। अभी तक विद्यालयीन स्तर पर नेट, एनबीए जैसे मूल्यांकन पद्धति नहीं थी लेकिन इस नीति में विद्यालयीन स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए एक संस्था बनाने की बात की गई। इसके साथ ही दो बार बोर्ड परीक्षा लेने का सुझाव दिया है। इस नीति में शिक्षा आयोग बनाने की वकालत की गई है (जिसकी मांग विद्यार्थी परिषद् लंबे समय से करती आ रही है)। शिक्षा आयोग तभी कारगर होगा जब न्यायालय एवं चुनाव आयोग की तरह स्वायत्त रखा जायेगा। क्योंकि सरकार बदलते ही नीतियां भी बदल जाती है। शोध पर शोध संस्थान बनाने की बात की गई है जिसे हर साल 20 हजार करोड़ अनुदान देने का सुझाव दिया है। शोध की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है लेकिन केवल आर्थिक अनुदान से ही शोध में सुधार आ जायेगा क्या? अभी जो शोध की स्थिति है उस पर यही कहूंगा कि शोध को भी एमए, एमएससी, एमकॉम की तरह डिग्री बना दिया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में छात्र परास्नातक के बाद शोध के बारे में सोचना शुरू करते हैं यहां तक कि अगर कोई छात्र शोध करना चाहे तो शोध का विषय भी उसके गाइड तय करते हैं, ऐसे में शोध की गुणवत्ता क्या रह जायेगी? शोध तो छात्रों का स्वाभाव होना चाहिए। शोध को विद्यालय स्तर से ही शुरूआत करना चाहिए तभी कुछ सार्थक परिणाम दिखेगा। अभी जो हालात है उस पर यही कह सकते हैं कि शोध भी अंग्रेजी में होगा। अगर अंग्रेजी में शोध होगा तो वह कट – पेस्ट ही होगा। क्योंकि छात्र असली शोध अपनी भाषा में ही कर सकता है। ड्राफ्ट में शिक्षा को तीन स्तर पर बांटने का सुझाव दिया गया है जो मुझे उचित नहीं लग रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय का काम ही शोधपरक शिक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इस

नीति में अलग – अलग संस्थान बनाने की बात की गई है। सरकार को चाहिये कि अलग – अलग संस्थान बनाने के बजाय जो संस्थान पहले से चल रहे हैं उसी में गुणात्मक सुधार करे। आर्टस, कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती है और इसके लिए उन्हें किसी से अनुमति की जरूरत नहीं होती है लेकिन अगर वही विश्वविद्यालय वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू करना चाहे तो उसे यूजीसी, एआईसीटीई इत्यादि से मान्यता लेना पड़ता है। मान्यता लेने/देने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यूजीसी, एआईसीटीई जैसे संस्थानों को मान्यता देने के बजाय अकादमिक सुधार पर काम करना चाहिए। यूजीसी, एआईसीटीई जैसे संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर निगरानी रखना और क्रमशः सुधार करना, होना चाहिए। मेरा मानना है जब तक शिक्षा को भारतीय भाषा में नहीं दी जायेगी तब तक शोध इत्यादि में गुणात्मक सुधार नहीं होगा क्योंकि सोचने की शक्ति किसी को भी उसकी मातृ भाषा में ही आती है। केवल नीति बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले भी दो नीतियां बनी, कई समितियां बनाई गई लेकिन विशेष सुधार नहीं हुआ इसका कारण क्या था? कारण था, नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होना। नीति बनाने से ज्यादा जरूरी है नीतियों का क्रियान्वयन होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति बने जो नीतियों को धरातल पर प्रयोग लाने में सहयोग करे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा मसौदा तैयार प्रस्तुत किया गया है। इस मसौदे का देश भर में स्वागत होना चाहिए और इसके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए जिसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। ■

(लेखक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव हैं एवं पूर्व में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं।)

विकास ऐसा हो जिसमें किसी का आत्मविश्वास न टूटे : श्रीनिवास

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि विकास का मौजूदा मॉडल न पर्याप्त है और न ही संतोषजनक । विकास की परंपरा में आधुनिकता का भी समावेश होना चाहिए । विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी का आत्मविश्वास न टूटे । इसमें मानवीय और जैविक सुरक्षा का भाव अंतरनिहित हो । विकास के वर्तमान ढ़ांचे में वातावरण की शुद्धता, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता का ख्याल और समानता की कमी महसूस हो रही है। उन्होंने ये बातें बिशुनपुर(झारखंड) स्थित विकास भारती में अभाविप के प्रकल्प विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कही। कार्यशाला का उदघाटन श्रीनिवास के साथ - साथ, अभाविप के आयाम प्रमुख देवदत्त जोशी, प्रख्यात पर्यावरणविद डॉ. प्रसाद देवधर आदि ने किया।

कार्यशाला में भाग ले रहे वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का उपयोग हमने भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए किया है । प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दौहन और दुरूपयोग के कारण आज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़ और सुखा का प्रकोप होना आम बात है । कार्यशाला में शामिल वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, भूगर्भ जल स्तर उठाने और नए उपकरणों का बढ़ाव देने पर भी बल दिया ।

विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) की अवधारणा पर चर्चा करते हुए अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद मराठे ने कहा कि विकास की अवधारणा समय के अनुसार परिवर्तित होते रहती है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास जगाने वाले अवधारणा को पुष्ट करने की जरूरत है। ■

जल संरक्षण पर दें ध्यान: अशोक भगत

तीसरे सत्र में पद्मश्री अशोक भगत के साथ उनके अनुभव और कथन पर परिचर्चा की गई और प्रतिभागियों ने उनसे प्रेरणा ली । अशोक भगत ने कहा कि जल संरक्षण पर हमें ध्यान देना होगा । स्थिति खराब होते जा रही है । यदि समय रहते नहीं चेते तो परिस्थितियां और भयावह होगी ।

राजस्थान : छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने लहराया जीत का परचम

राजस्थान के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को अप्रत्याशित सफलता मिली है । नौं में से पांच विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर अभाविप के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है । वहीं अगर महाविद्यालयीन छात्रसंघ चुनाव की बात करें तो 70 फीसद से अधिक महाविद्यालयों में अभाविप का परचम लहराया है । जबकि कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) को छात्रों ने लगभग नकार दिया है । अभाविप की मानें छात्रों ने मौसमी छात्र नेताओं को नकार दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि साल के 365 दिन उनके दुख-सुख में साथ रहने वाला एक मात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् है । राज्य के नौ बड़े विश्वविद्यालय में से पांच मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर में विद्यार्थी परिषद् ने परचम लहराया है बाकी चार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में निर्दलीय ने जीत हासिल की है । एनएसयूआई का सूपड़ा साफ हो गया । विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय छात्रसंघ को मिलाकर देखें तो अधिकांश जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रतिनिधि ही जीते हैं ।

अभाविप ने जयपुर प्रान्त के 3 में से 2 विश्वविद्यालय एवं 80 कैंपस में से 48 कैंपस में जीत दर्ज कि है अभाविप के जीत से पूरे प्रान्त में ख़ुशी की लहर है। राजस्थान में भरतपुर वृज विश्वविद्यालय में लगातार दूसरी बार अभाविप ने जीत दर्ज की यहां पर वृज विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर कविता फौजदार छात्रसंघ अध्यक्ष बनी इस प्रकार राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय. जगद्गुरु रामानन्दचार्य में पूरे पैनल का विजय हुआ है । अध्यक्ष के रूप में विजय शर्मा, उपाध्यक्ष के रूप में रवि शर्मा ,महासचिव के रूप में विजय वर्मा संयुक्त के रूप में जसप्रीत सिंह ने जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार जीत कर विश्वविद्यालय में हेट्रिक बनाई तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में संयुक्त सचिव किरण मीणा ने जीत दर्ज की ऐसे ही सीकर में कॉमर्स कॉलेज,कन्या कॉलेज,संस्कृत कॉलेज में जीत कर कम्यूनिस्टो को पछाड़ा है तथा सवाई माधोपुर में जिला केन्द्र का सबसे बड़ा कॉलेज पी.जी. कॉलेज में भी जीत दर्ज कि है । इस प्रकार अलवर, टोंक, दौसा

,करौली, धौलपुर जैसे प्रत्येक जिले में अध्यक्ष सहित सभी पदों पर बड़ी संख्या में जीत दर्ज करके अभाविप ने पूरे प्रान्त में परचम लहराया है एनएसयूआई से ज्यादा तो निर्दलीय उम्मीदवार विश्वविद्यालय में जीत कर आये है एनएसयूआई ने एक भी विश्वविद्यालय में जीत दर्ज नही की है । चितौड़ प्रांत के महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अभाविप ने जीत का डंका बजाया है । चितौड़ प्रांत के 82 महाविद्यालय में अभाविप के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा जिसमें से 50 महाविद्यालय में जीते एवं तीन विश्वविद्यालय जीते । चुनाव परिणाम के बाद परिषद् ने कहा है कि यह जीत उन तमाम कार्यकर्ताओं की है जो पूरे वर्ष कैम्पस में छात्र हितों में कार्य करते हैं। ■

हिमाचल प्रदेश: प्रांत स्तरीय जनजातीय छात्र सम्मेलन सोलन में संपन्न

सोलन में अभाविप के द्वारा प्रांत स्तरीय जनजातीय छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के श्रम रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं एवं लोकाचार के लिए जाना जाता है और यहां के निवासियों एवं युवाओं ने अपनी समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं को न केवल सहेज कर रखा है अपितु देश - विदेश को इनसे अवगत भी करवाया है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों से आग्रह किया कि वे विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में एकजूट होकर कार्य करें । ठाकुर की मानें तो जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए वर्तमान में 29 छात्रावास हैं जबकि 6 छात्रावास निर्माणाधीन है ।राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंश सिंह ब्रस्कोन ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा बजट का नौ फीसद व्यय किया जा रहा है । इस वर्ष जनजातीय उप योजना के तहत 639 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि लाहुल स्पीति जिले के विकास में रोहतांग सुरंग मील का पत्थर साबित होगी ।

वहीं अभाविप के अखिल भारतीय जनजातीय कार्य प्रमुख जे. राममोहन ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोग भारत के अभिन्न अंग है और इस समाज ने एक राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । जनजातीय समाज जल, जंगल और जमीन के रक्षक हैं । वनवासी समाज प्रकृति प्रेमी है और पर्यावरण की रक्षा में अहम योगदान दे रहे हैं । दूसरे सत्र में 'जनजातीय क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य' विषय पर प्रस्ताव प्रांत जनजातीय कार्य संयोजक आकाश नेगी ने जनजातीय समाज के छात्रों के समक्ष विचार हेतु रखा । जनाजातीय छात्रों की समस्याओं एवं जनजातीय क्षेत्रों में आम जनमानस की समस्याओं पर परिचर्चा और उनके समाधान पर अपने विचार रखे और विचारार्थ प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया । प्रांत संगठन मंत्री कोल नैगी ने सम्मेलन में छात्रों संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय नत्य की विभिन्न शैलियों में जहां मोहकता है तो गीतों में आनंद और उल्लास है । जनजातीय समाज अनुशासित और प्रकृति के उपासक होता है । इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद् का आधिकारिक दस्तावेज है और विद्यार्थी परिषद् का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रदेश सरकार से मिलकर उन्हें प्रस्ताव सौंपेगा ।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश ठाकुर ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं को कैसे संजो कर रखना है, जनजातीय समाज से सीखना चाहिए । देश के जनजातीय समाज के विकास बिना भारत

के विकास की गाथा अधूरी है । वहीं सत्र के अतिथि जवाहर लाल शर्मा ने कहा कि जनजातीय लोग न केवल संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहर होते हैं बल्कि वे सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी भी होते हैं जो जल, जंगल और जमीन की पूजा कर उनका कम से कम दोहन करते हैं । समापन सत्र के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । प्रांत जनजातीय सम्मेलन का आयोजन हिमाचल प्रदेश के सोलन में किया गया था जिसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्र पांगी, लाहौल - स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, कुल्लू इत्यादि जगहों से 260 जनजातीय छात्र - छात्राओं ने भाग लिया । ■

स्वतंत्रता दिवस की 73 वीं वर्षगांठ पर अभाविप ने निकाली तिरंगा रैली

स्वतंत्रता दिवस के 73 वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने देश भर में तिरंगा यात्रा रैली निकाली। पंजाब विश्वविद्यालय में अभाविप इकाई द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया । इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहा कि जहां एक तरफ वामपंथी भारत को तोड़ने की, अलग पंजाब की बात करते हैं वहीं पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस तिरंगा यात्रा के द्वारा देश की एकता और अखंडता का परिचय दिया है। डलहौजी (हि. प्र.) में कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए को हटाये जाने की जश्न में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली । भारत माता की जय व वंदे मातरम के जयघोष से गूंजती हुई व हाथों में बैनर, होर्डिंग्स लिए कार्यकर्ताओं की यह यात्रा महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर स्थानीय बाजार व बस स्टॉप से होते हुए वापस महाविद्यालय परिसर में जाकर समाप्त हुआ । कार्यकर्ताओं ने कहा आज आजादी के 73 वीं वर्षगांठ पर दोहरी स्वतंत्रता का आभास हुआ है । भारत माता के माथे पर लगे काजल के टीके 370 को बीते पांच अगस्त को हटाकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है । सरकार के इस निर्णय से अभाविप के भी वर्षों के आंदोलन की जीत हुई है ।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में पूरा बंगाल साराबोर रहा । इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिलीगुड़ी शाखा की ओर से 120 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गयी । 120 मीटर लंबी भारत की शान तिरंगे को अभाविप के सदस्यों ने पकड़ कर मार्च किया। कंचनजंघा स्टेडियम से निकली तिरंगा यात्रा हिलकर्ट रोड, सेवक रोड के रास्ते विधान रोड होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। अभाविप नांगल (इंद्रपुरा) के द्वारा 15 अगस्त को तिरूपति बाला जी मंदिर नांगल नदी से 101 मीटर का तिरंगा यात्रा निकाला गया । यात्रा का जगह – जगह पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया । नाचते गाते व भारत माता के जयकारे का नारे लगाते अभाविप के कार्यकर्ता तिरंगा के साथ शाकंभरी गेट मुख्यबाजार होते हुए वापस तिरूपति मंदिर पहुंचे । इस दौरान यात्रा ने लगभग पांच किलोमीटर का सफर तय किया ।

राजनगर इकाई द्वारा 281 फीट का विशाल तिरंगा लेकर पूरे इलाके में भ्रमण किया । भारत सरकार के जम्मू – कश्मीर पर ऐतिहासिक निर्णय का पूरे देश ने स्वागत किया गया । वक्ताओं ने कहा कि विगत 70 वर्षों से देश अनुच्छेद 370 खत्म होने के निर्णय का इंतजार कर रहा था । भारत सरकार ने 370 एवं 35 ए को हटाकर सराहनीय कार्य किया है । देश की आजादी के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए । श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक बलिदानियों ने निरंतर अथक परिश्रम किया। आज देश के वर्तमान सरकार के मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही ऐतिहासिक निर्णय संभव हो पा रहे हैं । कार्यकर्ता देश भक्त से ओत – प्रोत नारेबाजी की । तिरंगा यात्रा नीचे मुहल्ला से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पटेल गार्डन में भारती माता की भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ । यात्रा का नगर के प्रमुख स्थानों पर नगर के गणमान्य जनों ने स्वागत किया । यात्रा में युवाशक्ति तेज बारिश में भी उत्साह के साथ अपने हाथ में तिरंगा थाम कर चल रही थी । तिरंगा यात्रा का नेतृत्व प्रदेश मंत्री सतेन्द्र पटवा कर रहे थे । वहीं बाबुबरही में 150 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई । बाबूबरही से निकाली गई इस यात्रा को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी एक ओर स्कूली बच्चे आगे तिंरगा लहरा रहे थे वहीं दूसरी परिषद् के कार्यकर्ता विशाल 150 मीटर तिरंगे को थामे भारत माता की जय का उदघोष कर रहे थे । ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए आदर्श गुप्ता की रिपोर्ट)

असम : त्रुटिहीन एनआरसी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभाविप कार्यकर्ता

त्रुटिहीन एवं विदेशी मुक्त एनआरसी की मांग को लेकर अभाविप, असम के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया । प्रदर्शन के दौरान विदेशी मुक्त एनआरसी की मांग को लेकर गुवाहाटी के प्रमुख सड़क जीएस रोड पर जाम की स्थिति बन गई ।अभाविप की मांग है कि शुद्ध, त्रुटिहीन एनआरसी के लिए संबंधित कागजातों की शत – प्रतिशत पुनर्निरीक्षण की जाय । अभाविप ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी एनआरसी असम के समन्यवक प्रतीक हाजेला को सौंपा । कार्यकर्ताओं ने नगर के एसबी देवरा कॉलेज के पास से एक रैली निकाली जो भांगागढ़ स्थित एनआरसी समन्वयक कार्यालय के पास पहुंची। अभाविप के प्रदेश मंत्री राकेश दास ने कहा कि ने कहा, 'असम एक इस्लामिक राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है । मौजूदा एनआरसी ने यहां रह रहे बाहरी लोगों को जश्न का मौका दिया है वहीं बाकी लोग जो यहां के असल नागरिक हैं वो शिकायत कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके सभी दस्तावेज पूरे हैं लेकिन उनके नाम सूची में नहीं है। ये कैसे संभव है जबकि एक दशक पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में अवैध आप्रवासियों की संख्या 40 लाख से अधिक बताई थी। अगर इस एनआरसी को स्वीकार कर लिया गया तो ये असम के लोग अपने ही घर में प्रवासी की तरह हो जायेंगे।

सिस्टम और डेटा सुरक्षा पर बोलते हुए दास ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं। डेटा एंट्री को लेकर बड़ी चूक और समस्याएं रही हैं।'

हम अपनी पहचान के लिए 35 साल इंतजार कर चुके हैं, जरूरत पड़ने पर और एक साल तक इंतजार करेंगे पर हमें शुद्ध और विदेशी मुक्त एनआरसी चाहिए । उन्होंने कहा कि हमें एक भी अवैध विदेशी युक्त एनआरसी नहीं चाहिए तथा सभी स्वदेशी का नाम इसमें शामिल होना चाहिए। दास ने कहा, 'हमें एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है. हम चाहते हैं कि मूल नागरिक अपनी आवाज उठाएं. दरअसल, मोती उर रहमान केस नंबर 526/10 जो 1951 को 'कट ऑफ ईयर' के तौर पर माने जाने की मांग कर रहा है. हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं. हम असली तस्वीर और असम के लोगों के लिए इंसाफ चाहते हैं जो दशकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।'

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से अदालत से उपरोक्त आशय की मांग पहले ही की जा चुकी है परंतु कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था । उसके बाद विभिन्न संगठनो की ओर से इस तरह की मांग तेज हो गई है । ■

क्या हांगकांग में जारी छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार पाने में सफल होगा?

पिछले दिनों हांगकांग प्रशासन एक विधेयक लेकर आया था, जिसके मुताबिक अगर हांगकांग का कोई व्यक्ति चीन में कोई अपराध करता है या प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ हांगकांग में नहीं बल्कि चीन में मुकदमा चलाया जाएगा। इस विधेयक के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर है। सड़कों पर हो–हल्ला मचा हुआ है। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने हवाईअड्डे पर भी कब्जा कर लिया था। पिछले कई दिनों से यहां की सड़कों पर लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व 23 वर्षीय छात्र नेता जोशुआ वांग कर रहा है। जोशुआ वांग के नेतृत्व में किये जा रहे इस आंदोलन ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोगों में लोकतंत्र के बहाली की उम्मीद जगी है। आंदोलन के बीच सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है कि क्या हांगकांग में जारी छात्र आंदोलन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पाने में सफल होंगे या फिर थ्यानआनमन की तरह इस आंदोलन को भी कूचल दिया जायेगा। उक्त मुद्दे को लेकर "राष्ट्रीय छात्रशक्ति" के स. संपादक अजीत कुमार सिंह ने देशभर के लोगों से बात की और उनके विचार जाने। प्रस्तुत है कुछ चुनी हुई प्रतिक्रियाएं –

चीन हमेशा से हर जगह किसी भी तरीके से अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। मानवीय संवेदनाएं व जीवन मूल्य उसके लिए शुन्य है। हांगकांग के मानवाधिकार पर आघात करने की पूरी कोशिश चीन द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि हांगकांग चीन का एक स्वायत्त द्वीप है परंतु "एक देश – दो व्यवस्था" की अवधारणा के साथ हांगकांग को अपनी स्वतंत्रता सामाजिक, कानूनी और राजनैतिक रखने की गांरटी दी गयी थी। हांगकांग निवासी भी स्वयं को चीन का हिस्सा नहीं मानते। इसके बावजूद चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने हांगकांग सरकार पर विपरीत प्रभाव डाला है। छात्र हमेशा से जन – जन की आवाज रहा है। छात्र आक्रोश के रूप में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराने की मांग को लेकर खड़े हुए तीन छात्र के साथ पूरा युवा समाज खड़ा है। यह आक्रोश है हांगकांग और चीन के बीच प्रत्यर्पण को लेकर बनाए गए नये कानून को लेकर। जिसमें हांगकांग में संदिग्ध पाए गए लोगों की आसानी से प्रत्यर्पण कर चीन ले जाया जा सकेगा परंतु हांगकांग में छात्र व युवा समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जब एक विद्यार्थी आवाज उठाता है, उसका साथ पूरा समाज समाज देता है। निश्चित ही विद्यार्थियों द्वारा उठाई गई ये आवाज सफलता देगी और हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना होगी।

-ग्रीष्मा त्रिवेदी, शोध छात्रा (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर)

चीन ने वन नेशन थ्योरी के तहत हांगकांग, मकाऊ और तिब्बत का जबरन अधिग्रहण किया है, इसलिए वहां के लोग खासकर हांगकांग के छात्र – युवा जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, पूरी तरह जायज है। हांगकांग में चल रहे प्रदर्शन, चीन की वामपंथी सरकार के निरंकुशता के खिलाफ होना स्वाभाविक है। यह आज नहीं तो कल होना ही है। वर्ष 1989 में राजधानी बीजिंग के थ्यानआनमन चौक पर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर उनके प्रदर्शन को दबाने के लिए चीनी सेना ने चार जून को टैंक चढ़ा दिए थे। इस बर्बर घटना में कितने लोगों की जान गई इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। अस्सी के दशक और वर्तमान की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है, चीन उस समय विरोध की आवाज को दबाने में इसलिए सफल हो पाया क्योंकि उस समय इतनी मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि नहीं था। चीन अभी अमेरिका के साथ ट्रेड वार, भारत के साथ सीमा विवाद एवं अपने देश के अंदरूनी मामले में फंसा हुआ है इसलिए हांगकांग की आवाज को थ्यानआनमन की तरह दबाने का भूल नहीं करेगा। छात्रों के प्रदर्शन का परिणाम क्या होगा, पता नहीं लेकिन इस प्रदर्शन ने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

- **किशोर झा, प्रतियोगी छात्र** (मुखर्जी नगर, दिल्ली)

हांगकांग में चल रहा आंदोलन आजादी के आंदोलन से भी बढ़कर है। इस आंदोलन ने विश्व बिरादरी का ध्यान हांगकांग की ओर खिंचा है और निश्चित रूप से यह प्रदर्शनकारियों की आंशिक जीत है। प्रदर्शनकारी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर पायेगा या नहीं यह कहना मुश्किल है लेकिन चीनी सरकार को इस आंदोलन ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। कूटनीति या अन्य कारण से भले ही कोई देश कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन उसका ध्यान पूरे घटनाक्रम पर है। चीन, जहां पर मीडिया तक को आजादी नहीं है, लोकतंत्र का तो दूर – दूर तक वास्ता नहीं वह दूसरे देशों के मामले में टिप्पणी करता है और अपने ही देश में इससे मुकर जाता है। यह समय है विश्व समुदाय के सामने चीन के कुत्सित चालों को एक्सपोज किया जाय। हांगकांग का आंदोलन समान्य आंदोलन नहीं है इसका सामरिक महत्व है। मेरे विचार से दुनिया के तमाम छात्र संगठनों एवं संस्थाओं को हांगकांग के छात्रों द्वारा चलाये जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि हांगकांग के युवा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। हांगकांग की घटना को देखकर मुझे जेकोस्लाविया की घटना की याद आ रही है जब जेकोस्लाविया में नरसंहार हो रहे थे तब विश्व के तमाम देश, यूएनओ सहित अन्य संस्थाएं चुप बैठी थी, विश्व समुदाय को इस पर कदम उठाना चाहिए खासकर यूएन को। 1989 में थ्यानआनमन में प्रदर्शनकारियों को बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिये गये थे कहीं वह हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के साथ भी ऐसा न कर बैठे, इसलिए यूएन के आर्टिकल (एक) के तहत इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए।

- **आदित्य कुमार, अधिवक्ता** (दिल्ली हाइकोर्ट)

हांगकांग में अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए भारी संख्या में वहां के युवा – छात्र सड़क पर है। छात्रों की मांग है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल किया जाय और हांगकांग प्रशासन द्वारा जारी विधेयक वापस लिया जाय। वहां के छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और धीरे – धीरे यह प्रदर्शन व्यापक रूप ले रहा है। इस आंदोलन ने चीनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि दुनिया भर में भारत सहित अन्य देश को मानवाधिकार की पाठ पढ़ाने वाले चीन अपनी ही जनता के साथ ज्यादती कर रही है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। इस आंदोलन ने लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों में एक उम्मीद जगाई है। आशा करता हूं छात्रों का आंदोलन सफल हो और चीनी सरकार उन्हें उनकी लोकतांत्रिक अधिकारों को मुहैया कराये।

- **एम. वेंकटेश** (तिरूपति, आंध्रप्रदेश)

तिरंगा यात्रा

RNI No.: DELBIL/2017/73636
Date of Posting: 10-11 September, 2019
Date of Publishing: 8 September, 2019

Postal Regd. No.: DL(C)-11/1409/2017-2019
Post Office: NDGPO, New Delhi

Come, fall in love with the Snow Fall

HIMACHAL TOURISM

Winter in Himachal is like a paradise for tourists where the charm and adventure of playing in the snow will make you fall in love with life again! Snowcapped mountains, frozen lakes and mesmerizing scenes of the valleys will simply take your breath away.

Kalpa (Kinnaur)

DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION
Block No 28, SDA Complex, Kasumpti, Shimla (H.P.).
Phone: 0177-2625924, 2623959, 2625511, 2625864; Fax: 0177-2625456
Email: ***tourismmin-hp@nic.in; tourism.hp@nic.in***

For all accommodation requirements and packages
visit: ***www.hptdc.in; www.himachaltourism.gov.in***

Unforgettable Himachal